satisfactory. The major reasons for poor recovery are reported to be inadequate income generation, costly maintenance, high input prices defective assets and unexpected natural calamities, ' diversion of income for meeting more urgent consumption needs etc. The Government has taken adequate care to guard against the misuse of IRDP funds by calling regular reports regarding action taken on cases of corruption/misutiljsation/ma!nractices involving IRDP funds. The Government of India has also advised the States to assist banking sector in the recovery of the loans under I.R.D.P.

Statement

Families assisted under Integrated Rural Development Programme during the last three years

Year	Total families assisted (No. in lakhs)	%of SC/ST families assisted
1990-91	28.98	49.90
1991-92	25.37	51.08
1992-93	20.69	51.41

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय मकानों की कमी

3250. **श्री राम जेठमलानी :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पहली मार्च, 1991 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 206 लाख आवासीय मकानों की कमी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि सर्वेक्षण के अनुसार बढ़ती आबादी के कारण प्रति वर्ष अनुमानत: 20 लाख अतिरिक्त आवासीय मकानों की आवश्यकता होती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की इस समस्या को हल करने हेतु कोई योजना तैयार की है ;

(घ) यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने आवासीय मकान बनाये जाने का लक्ष्य है ; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितने आवासीय मकानों की कमी होगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास की योजनाएं अलग-अलग राज्य सरकारों में अलग-अलग हैं । उनके प्रयासों में सहायता देने के उद्देश्य से कमजोर वर्गों के लिए चल रहे आवास कार्यक्रमों के लिए [illegible]/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने का एक योजना तैयार की जा रही । इस योजना के ब्यौरे इसे अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे ।

(ङ) ऐसी आशा है कि इस योजना से आवास की कमी में और गिरावट आएगी ।